



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

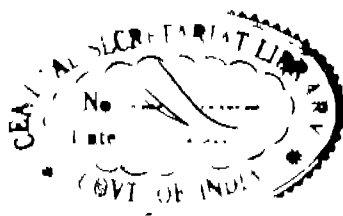
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 1976/फाल्गुन 15, 1897

No. 108]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 1976/PHALGUNA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th March 1976

S.O. 171(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No. S.O. 1027, dated the 6th March, 1971, read with the order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Heavy Industry) No. S.O. 170 (E) dated the 5th March, 1976, the management of the industrial undertaking known as Messrs Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 5th day of March, 1977;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Heavy Industry) No. S.O. 232(E) dated the 28th May, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the 6th day of March, 1971, shall remain suspended upto the 5th of March, 1976 and that all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period of one year up to the 5th March, 1977.

[No. F.4/7/76-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1976

का० आ० 171 (अ).—भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं० का० आ० 170 (ई) तारीख, 5 मार्च, 1976 के साथ पठित, भारत-सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1027, तारीख 6 मार्च, 1971 द्वारा मैसर्स ब्रेथर्वेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के अधीन 1977 की मार्च के पांचवें दिन तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं० का० आ० 232 (अ), तारीख 28 मई, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित किया था कि प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार था या जो 6 मार्च, 1971 से ठीक पूर्व उसे लागू थी, 5 मार्च, 1976 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी या उनमें से कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 5 मार्च, 1977 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाती है।

[पा० सं० 4/7/76—सीयूसी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।